पीड़ित किसानों को हर प्रकार की राहत तथा क्षतिपूर्ति की जाये। साथ ही ऐसे क्षेत्रों के किसानों का राजस्व एवं अन्य देयों की वसूली स्थगित कर दी जाये।

Need for more postal telecommunications facilities in Mahbubnagar district of Andhra Pradesh

SFRI PUTTAPAGA RADHAKRI-SHNA (Andhra Pradesh); Thank you, Mr. Vice Chairman, Sir, for giving me aa opportunity to make my special mention. I hail from the Mahbubnagar district of Andhra Pradesh. I would like to draw the attention of the Communications Ministry to some problems faced by my district, Mahbubnagar. Sir, Mahbubnagar is a vast district with 25 lakhs of population and more than 1500 revenue villages, apart from colonies and hamlets. But it is having only two postal divisions, which are not sufficient for it. That is why I request the hon. Minister of Communications, through you. to take steps to create another postal division in Mahbubnagar district, with head-quarters at Nagarkurnool. Apart from that, there are 64 mandal headquarters in the district which are growth (centres for which an effective communication system is also required. That is why I request the Minister, through you, to take steps to open sub post offices at all mandal headquarters in the district Already most of the mandal headquarters are having sub offices. 1 request the Minister to cover the remaining headquarters also with sub post offices.

Coming to telecommunications, unlike the other parts of the country, Mahbubnagar district is not having effective telecommunications, particularly telephones. That is why I request the Minister to take effective steps to increase the efficiency of telecommunications in my district. In this connection, I want to mention that the important towns are Vanaparthy, Na-garkurnool, Gadwal. Shadnagar. They are not having STD provision in the telephones. That is why I request the Hon. Minister, through you, to take effective steps to provide STD facilities in telephones to all these four towns, namely, Vanaparthy, Nagarkurnool, Gadwal and Shadnagar.

Sir, I want to make another request that most of the villages, even major villages are not covered by post offices. There should be provision of post offices in all major villages, and any such major village which does not have a Pos* office should be provided one.

Lastly, Sir, I want to request the Government to provide PCOs and telephones at all the mandal head-ouarters, if not in all villages. For villages, I do not request at this stage. But I request PCOs at all mandal head-quarters in the district. It does not require large allocations as most of the mandal headquarters are already having this facility. Thank you.

Need for remunerative prices to Potato Growers in U.P.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) मान्यवर, में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सरकार का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह प्रश्न किसानों से संबंधित है। किसान इस देश की रीढ़ है और इस देश की अर्थ व्यवस्था बहुत कुछ कृषि जन्य वस्तुओं और उनसे संबंधित उद्योगों पर निर्भर करती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस देश का किसान जितना उत्पादन बढ़ाता है उतना ही मारा भी जाता है। उसी कड़ी में इस साल आलू का उत्पादन 1 लाख 20 हजार टन होने का अनुमान है और उत्तर प्रदेश में करीब पूरे प्रदेश में जितना आलू पैदा होता है उसका 50 फीसदी उत्तर प्रदेश में पैदा होता है और उसका भी 45 प्रतिशत फरुखाबाद इलाहाबाद और उनके अगल-बगल के इलाकों में और मेरठ में भी काफी आलू पैदा होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में किसानों के सामने परेशानी पैदा हो गई है। सरकार ने यह घोषणा की है कि 70 रुपए में नाफेड के द्वारा आलू खरीदा जाएगा,

[श्री राम नरेश यादव]

लेकिन नाफेड की व्यवस्था कागज पर ही रह गई है। कहीं पर भी नाफेड के द्वारा खरीद नहीं हो रही है। इसका असर यह पड़ रहा है कि देहातों में किसान मजबूर होकर 50-50 रुपए क्वींटल के भाव पर आलू बेच रहा है। दूसरे कोल्ड स्टोरेज की भी व्यवस्था नहीं है। दूसरे कोल्ड स्टोरेज वालों ने अपने शीत गृहों पर यह लेवल लगा दिये हैं कि आलू का भंडारण नहीं होगा। इसका नतीजा यह हो गया है कि आलू के बोरे महीनों बाहर पड़े रहते हैं और आलू सड़ रहा है, उस पर दुर्गन्ध आ रही है। इस प्रकार से किसान मारा जा रहा है।

दूसरी बात म यह कहना चाहता हूं कि आज तक सरकार ने जब आलू का उत्पादन बढ़ जाता है तो उसके संकट के निवारण के लिए, उसकी खरीद के लिए, कोई उद्योग नहीं लगाया है। इसलिए मेरी यह मांग है कि सरकार ने जो 70 रुपए क्वींटल नाफेड के द्वारा खरीदने की बात की है, वह दाम बहुत कम हैं। जैसाकि कानपुर के प्रौद्योगिकी और विज्ञान महाविद्यालय ने दो साल पहले 87 रुपए नियत किया था, लेकिन सरकार ने सौ रुपए भी नहीं किया और 70 रुपए में सरकार खरीद भी नहीं रही हैं। मतलब यह है कि सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। जानबूझ कर किसानों के सामने यह समस्या पैदा की जा रही है कि वे पैदावार न बढ़ायें। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह किसानों का आलू खरीदने की व्यवस्था करे ताकि जो 60 लाख टन आलू प्रदेश में पैदा हुआ है वह बाहर भेज कर बेचा जा सके। मेरी सरकार से यह भी मांग है कि इन इलाकों में सरकार इंडस्ट्री लगाने पर गम्भीरता से विचार करे और इसके लिए योजना बनाए। आलू उत्पादक किसान आज जिस तरह से मारा जा रहा है और इस सरकार के राज में उनको जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनको दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने चाहिए। इन क्षेत्रों में जन शक्ति भी अपार है। किसानों और मजदूरों को काम दिया जाना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन क्षेत्रों में उद्योग लगाये जाये। इन शब्दों के साथ मेरा सरकार से आग्रह है कि इन चीजों पर ध्यान दिया जाए और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाये जाये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी यादव साहब ने जो स्पेशल मेंशन उठाया है, आप जानते हैं कि कोल्ड स्टोरेज वालों को सरकार बड़े पैमाने पर बिजली देती हैं, कर्जा देती है, उनकी स्थापना में सहायता देती हैं, लेकिन कोल्ड स्टोरेज वाले अपने भंडारों में आलू नहीं रखते हैं, बल्कि अब उन्होंने गुड़ रखना शुरू कर दिया है। उसका नतीजा यह होता है कि सस्ते भाव पर गुड़ रख लेते हैं और बाद में ऊंचे भाव पर बेच देते है। इसका नतीजा यह भी हो रहा है कि जो पैरिशेबल कमोडिटीज हैं वे बाहर पड़ी रहती हैं। इसलिए मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि हर हालत में इन कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा जाय और उसके बाद में कोई अन्य चीज रखी जाय। हर हालात में आलू के रखने की व्यवस्था की जाय।

Plight of Labourers working in Salt Industry in Gujarat

श्री मीर्जा इर्शादबेग (गुजरात) : मान्यवर, आज से 58 वर्ष पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जीवन की अत्यन्त आवश्यक वस्तु नमक पर लगाये कर तथा नमक उत्पादन के एकाधिकार के विरुद्ध आन्दोलन चलाया तथा ऐतिहासिक डांडी कूंच का आयोजन किया। इसी नमक उत्पादन से संबंधित मजदूरों की दयनीय स्थिति के उन्मूलन के संबंध में मै इस विशेष उल्लेख से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, समग्र देश में 70 लाख टन नमक का उत्पादन होता है जिसका 60 से 66 प्रतिशत उत्पादन गुजरात करता है और